(1400/SM/CP)

1401 hours

The Lok Sabha re-assembled at one minute past Fourteen of the Clock.

(Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

1401 hours

(*At this stage,* Adv. Dean Kuriakose, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Benny Behanan *and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1401 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid.

Item no. 2. Shri Arjun Ram Meghwal.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ. 1004(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी एचएस 0106 90 00 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(2) का.आ. 1145(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।

(3) का.आ. 1463(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द दाल (एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हिप्पर की फलियां) [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 3110] और तूर/अरहर [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 60 00] (केजैनस कजान) की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(4) का.आ. 1559(अ) जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(5) का.आ. 2031(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत आईटीसी (एचएस) कोड 71123000, 71129100, 71129200, 71129910, 71129920 और 71129990 की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(6) का.आ. 2053(अ) जो 02 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 के अंतर्गत उपबंधों की छूट को विस्तारित किये जाने के बारे में है।

(7) का.आ. 2320(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत ताजा अदरक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(8) का.आ. 2357(अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(9) का.आ. 2378(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 में नीति शर्त के समावेश और कागज की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(10) का.आ. 2821(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के अंतर्गत तरबूज बीजों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(11) का.आ. 1549(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध थी, का विस्तार 30 सितम्बर 2022 तक करने के बारे में है।

(12) का.आ. 1269(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अनुसूची-दो अध्याय-10 क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(13) का.आ. 1270(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2018 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत निर्यात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।

(14) का.आ. 2162(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(15) का.आ. 2235(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(16) का.आ. 2236(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(17) का.आ. 2321(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांस चारकोल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(18) का.आ. 2375(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीनी की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(19) का.आ. 2985(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची दो के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

1. The Aadhaar (Authentication and Offline Verification) (First Amendment) Regulations, 2022 (No. 01 of 2022) published in Notification No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022) in Gazette of India dated 4th February, 2022.
2. The Aadhaar (Enrolment and Update) (Ninth Amendment) Regulations, 2022 (No. 2 of 2022) published in Notification No. HQ-16041/4/2021-EU-I-HQ-Part(I)(No.2 of 2022) in Gazette of India dated 3rd March, 2022.
3. The Aadhaar (Appointment of Officers and Employees) (Second Amendment) Regulations, 2022 (No. 3 of 2022) published in Notification No. F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No.3 of 2022) in Gazette of India dated 21st March, 2022.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.402(E) in Gazette of India dated 30th May, 2022 under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

(2) A copy of the Low Power Radio Frequency Devices in the frequency band 433.05 to 434.79 MHz (Exemption from License) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.347(E) in Gazette of India dated 11th May, 2022, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 and sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.

… (*Interruptions*)

ASSENT TO BILLS

1403 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I lay on the Table the following seven Bills passed by the Houses of Parliament During the Eighth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd February, 2022:-

1. The Appropriation (No.2) Bill, 2022;
2. The Appropriation (No.3) Bill, 2022;
3. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022;
4. The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022;
5. The Finance Bill, 2022;
6. The Appropriation Bill, 2022; and
7. The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2022.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of the following four Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

1. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022;
2. The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022;
3. The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022; and
4. The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE -- contd.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या 17/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना संख्या 18/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) अधिसूचना संख्या 19/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं, नामत: पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से निर्यात किए जाने पर सड़क और अवसंरचना उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) अधिसूचना संख्या 20/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

… (<u>व्यवधान</u>)

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

51st and 52nd Reports

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2022-23):-

(1) Fifty-first Report on 'Assessment of Assessees in Entertainment Sector (DT)'.

(2) Fifty-second Report on 'Construction and utilization of Limited Height Subway (LHS)'.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 357TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 357th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

… (*Interruptions*)

(1405/KKD/NK)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENTATIONS IN 11TH AND 19TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID

1406 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my colleague, Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on 'Price Rise of Essential Commodities - Causes and Effects' pertaining to the 3 Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

MOTION RE: 34TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1407 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my senior colleague, Shri Pralhad Joshi, I beg to move the following:-

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July, 2022."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July, 2022."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377

1407 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Matters under Rule 377.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohanbhai Kundariya to raise his matter.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is not proper.

… (*Interruptions*)

Re: Need to Provide Lift Irrigation Facility in Gujarat Particularly in Rajkot And Morbi Districts

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): आदरणीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान नहर सिंचाई (बांध) की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। राजकोट और मोरबी जिलों सहित पूरे गुजरात में नहर सिंचाई (बांध) के स्वरुप में खेती के लिए जल आपूर्ति की जाती है। … (व्यवधान) अगर जल की आपूर्ति प्रधान मंत्री सिचाई योजना के अंतर्गत लिफ्ट इरीगेशन में कन्वर्ट की जाये तो ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के लिए उपयोग में लायी जा सकती है और किसानों की आय में बढोत्तरी एवं फसल के उत्पादन में मददगार साबित हो सकती है।

अतः मैं आप के द्वारा किसान हितैषी नहर सिंचाई (बांध) को लिफ्ट इरीगेशन में जल्दी से जल्दी परिवर्तित करने का निर्देश माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा देने की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Condition of Schools in Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): माननीय सभापति महोदय, कांकेर जिले के प्रत्येक विकास खंड में पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इगनाईट अंग्रेज़ी माध्यम के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में यदि कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंड के दर्ज आंकडे प्रस्तुत करें तो 1685 है। … (व्यवधान)

इसी प्रकार छतीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिलों के विकास खंडों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की लगभग दर्ज संख्या 65000 है। लेकिन चार वर्ष पहले खुले अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों के लिए न विद्यालय भवन है, न ही जगह है, ना शिक्षक और ना ही अधोसंरचना विकास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई पहल की जा रही है। वर्तमान में इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। … (व्यवधान)

दूसरी ओर छतीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाने पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। … (व्यवधान) लेकिन उक्त स्कूलों के प्रति शासन-प्रशासन उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

अत: सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि पूरे राज्य के विकास खंडों मे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इगनाईट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षक, भवन एवं शौचालय तथा आवश्यक अद्योसंरचना का विकास किया जाए, जिससे गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त हो सके।

(इति)

(1410/SK/RP)

Re: Construction of Ramganjmandi-Bhopal Railway Line

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): माननीय सभापति जी, भारत सरकार द्वारा रेलवे की महत्वकांक्षी परियोजना, रामगंजमंडी-भोपाल जी 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक लाकर बंद कर दी गई थी जिसे 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ कर फास्टट्रैक में शामिल किया गया है। विभागीय उदासीनता के कारण रामगंज मंडी परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। अत: माननीय रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपया इसे गति देकर शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Converting NH-351 in Gujarat into Four Lane Road

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): माननीय सभापति जी, आपका ध्यान केन्द्रित करते हुए बताना है कि नेशनल हाईवे NH-351 महुवा-सावरकुंडला-अमरेली-वडिया-जेतपुर जो कि 2015 में प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया था उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसका अलाईमेंट फरवरी 2019 में फाइनल हुआ जिसको एनएचएआई के अनुसार ट्रैफिक कम होने की वजह से उनको फॉर लेन में तब्दील करने के लिए रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मैंने अधीक्षक इंजीनियर के साथ मीटिंग की और उनको ये समस्या बताई तो उनकी ओर से 9, 10 और 11 नवम्बर 2021 को वापस ट्रैफिक सर्वे किया गया जिसमें अमरेली और सावरकुंडला के बीच 1200 पिसियू से ज्यादा ट्रैफिक आया था उसको देखते ये ट्रैफिक फोर लेन का मालूम पड़ता है। उससे पहले जो ट्रैफिक सर्वे करवाया था वो लॉकडाउन की वजह से कम आया था इसलिए उनको रिजेक्ट किया था। परन्तु फरवरी और मार्च 2021 की अगर रिपोर्ट देखें तो ये ट्रैफिक फोर लेन का लगता है। दूसरा, अभी हाल में जो रोड है वो 10 मीटर की ही है और अभी जो वार्षिक योजना की घोषणा हुई उसमें भी ये रोड 10 मीटर की ही बन रही है। महोदय ज्ञात है यह रोड पूरे जिले की एक मात्र रोड है जो गुजरात के पिपावाव पोर्ट को जोड़ती है और भी कई जीआईडीसी है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस रोड को नए रूप से 45 मीटर जमीन अधिग्रहण कर के फोर लेन बनाया जाए क्योंकि ये अमरेली जिला का एक मात्र नेशनल हाईवे है और इसका ट्रैफिक भी ज्यादा है। अभी जो घोषणा हुई है इसमें सिर्फ पैसा खर्च होगा ट्रैफिक का सुधार नहीं होगा। इस रोड को जनहित में और अगले समय को ध्यान में रख के बनाया जाए जिससे पैसे की बर्बादी ना हो और लोगों को सुविधा मिल सके।

(इति)

माननीय सभापति (श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी): श्री रमेश बिन्द

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: श्री एस. मुनिस्वामी

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: श्री बिद्युत बरन महतो

… (<u>व्यवधान</u>)

Re: Need to construct a pit line at Latur Railway Station.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): माननीय सभापति जी, लातूर स्टेशन पर पिटलाइन बनाने की मांग बहुत पुरानी है पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण विगत 70 साल से यहां पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है।

लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइ- के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ना संभव हो जाएगा।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Hon. Members, please take your seats. These are very important issues.

… (*Interruptions*)

(1415/MK/NKL)

Re: Expansion of Kishangarh Airport in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर, राजस्थान में स्थित किशनगढ़ हवाईअड़े से वर्तमान में दिल्ली-अहमदाबाद-हैदराबाद-इन्दौर-सूरत एवं मुम्बई की नियमित हवाई सेवायें चल रही हैं। लेकिन, देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिये नियमित उड़ानें प्रारम्भ नहीं होने से एयरपोर्ट का समग्र उपयोग नहीं हो पा रहा, जबकि उक्त एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के चलते एयरपोर्ट के रनवे एंव टर्मिनल विस्तार की कवायद विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। लेकिन, रनवे विस्तार कार्य में ग्राम टूकडा की 02 पहाड़ियों की चोटियों की कटाई एव ग्राम गगवाना में स्थित प्रसार भारती के आकाशवाणी टॉवर की ऊंचाई कम करने अथवा अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि उक्त दोनों ही अड़चनों को दूर करने के लिये एयरपोर्ट ओथोरिटी एवं राज्य सरकार के द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण के साथ-साथ दो बार प्रशासनिक स्तर पर सर्वे भी कराया जा चुका है और वर्तमान में उक्त दोनों पहाड़ियों की कटाई के लिये वन-विभाग की एन.ओ.सी एवं आकाशवाणी के टॉवर के स्थानान्तरण की पत्रावली विभागीय स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

अतः व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किशनगढ़-अजमेर एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही उक्त दोनों बाधाओं को दूर कराकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र सकारात्मक विभागीय कार्यवाही करायी जाये तो इस परियोजना पर हुआ करोड़ों रुपयों का निवेश बहुउपयोगी साबित होगा।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil – Not Present

… (*Interruptions*)

Re: Conversion of NH-28 from Mazaffarpur to Barauni into Four-Lane

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से होते हुए बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 को फोर लेन में तब्दील करने की आवश्यकता है।

महोदय, यह सड़क माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरीराज सिंह जी के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के फोर लेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों के समग्र विकास को गति मिलेगी। उक्त राजमार्ग को फोर लेन में तब्दील करने की चिर प्रतीक्षित मांग से माननीय सड़क परिवहन एवम् राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व्यक्तिगत तौर से अवगत हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुजफ्फरपुर के एक सभा में मेरी मांग पर मंच से हजारों लोगों की उपस्थिति में इसको फोर लेन में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी इस संबंध में उठाए गए सकारात्मक कदम की चर्चा के अलावा भौतिक रूप में कुछ भी काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में जब माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हम सड़क के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश को नाज हो रहा है। ऐसे में जमीन पर कोई कार्य दिखाई नहीं देने से आम जनों में आक्रोश व्याप्त है।

आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जनहित में यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के कार्यारंभ की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए।

(इति)

(1420/SJN/MMN)

Re: Scheduled Tribe status to Lohara caste in Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लोहार समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सन् 1950 ई. में रोमन लिपी में Lohara जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिस तरह से केरल को Kerala, कर्नाटक को Karnataka, योग को Yoga इत्यादि लिखा जाता है, इसी तर्ज पर लोहार को संविधान में Lohara लिखा गया। लेकिन सन् 2006 में संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 के द्वारा Lohara का हिन्दी रूपांतरण लोहारा कर दिया गया, जिसके कारण लोहार समाज को मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का अधिकार छिन गया। क्योंकि बिहार में लोहारा और लोहरा नाम की कोई जाति निवास नहीं करती है। ऐसी परिस्थिति में लोहार समाज के लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। बिहार में लोहारा या लोहरा जाति नहीं पाई जाती है और न ही लोहारा, लोहरा के निवास, जनसंख्या एवं भूमि संबंधित दस्तावेज ही बिहार सरकार के पास उपलब्ध है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 को रद्द कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे कि लोहार (Lohara) जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति के रूप में खोया हुआ अधिकार मिल सके। (इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Shrimati Riti Pathak - Not present.

Re: Setting up of Integrated Manufacturing cluster in Garhwa district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में सेल के 1,180 हेक्टेयर भूमि पर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDC) के तहत (Amritsar-Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में (NICDC) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, भारत सरकार, श्री अमृत लाल मीना ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना के संबंध में 6 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा था। विदित है कि उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा ने उक्त बिन्दुओं पर झारखंड सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना से झारखंड राज्य के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन संभावित है एवं राज्य का संतुलित विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा एवं उद्योग के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे गढ़वा जिला आकांक्षी जिलों की सूची से बाहर निकल सकेगा एवं राज्य के अन्य विकसित जिलों में आ खड़ा होगा। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना हेतु अग्रतर कार्रवाई कराने की कृपा की जाए। (इति)

… (व्यवधान)

Re: Need to upgrade schools in Maharajganj parliamentary constituency in Bihar as PM Shri Schools

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत सारण प्रमंडल के जिला-सारण (छपरा) एवं जिला-सिवान में परिसीमित मेरा लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज है। इसी प्रमंडल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, देश को दूसरी आजादी दिलाने वाले लोकतंत्र के रक्षक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं महान शिक्षाविद मौलाना मजहरूल हक की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रहा है। ऐसे महान विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली तथा मेरे लोक सभा की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। बिहार तो वैसे ही अति पिछड़ा राज्य है, उसमें भी मेरा लोक सभा क्षेत्र हर क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल एवं क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2024 तक देश के सभी प्रखंडों में "PM-श्री" स्कूल के नाम से आदर्श स्कूलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही लाभकारी एवं जनहितकारी योजना है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इस योजना के तहत मेरे लोक सभा के क्षेत्र के सभी प्रखंडों जैसे - पानापुर, तरैयां, मशरक, बनियापुर, लहलादपुर (जनताबाजार), एकमा, मांझी, जलालपुर, भगवानपुर हाट, महराजगंज, बसंतपुर, लकड़ीनवीगंज एवं गोरेयाकोठी में से एक-एक विद्यालय को चयनित कर उक्त योजना के तहत अपग्रेड किया जाए। अत: माननीय सभापति महोदय के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में "PM-श्री" स्कूल उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए, जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने में सरकार का सराहनीय सहयोग मिल सके। (इति)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

(1425/VR/YSH)

Re: Payment of claims to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Mahasamund parliamentary constituency, Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): महोदय, देश की कृषि ज्यादातर मौसम पर निर्भर करती है।... (व्यवधान) अनेकों बार किसानों की फसल अल्प वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है और किसान कृषि कार्य करने में निःसहाय हो जाते हैं।... (व्यवधान) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' वर्ष 2016 में लागू कर किसानों को राहत देने का कार्य किया गया है, लेकिन इसमें भी राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित ग्रामों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि को समय पर नहीं देना कृषि कार्य को कमजोर करना है।... (व्यवधान) किसानों के लिए यह एक अभिशाप ही है। महोदय जी, छत्तीसगढ़ में मेरे लोकसभा महासमुंद क्षेत्रांतर्गत कृषकों को पिछली फसल के समय जिन ग्रामों में अल्प वर्षा के कारण फसल नहीं हुई है, अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने के कारण किसान काफी आक्रोशित हैं, जिन्हें वर्तमान में कृषि के लिए बीज, खाद्य एवं कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने की अति आवश्यकता है।... (व्यवधान) वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर किसान कृषि कार्य से पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण किसान आज योजना से वंचित होकर खुद ठगा सा महसूस कर रहा है।... (व्यवधान) अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अतिशीघ्र प्रदान कराने हेतु निर्देशित करें, ताकि किसानों को अपने कृषि कार्य करने में उक्त योजना का लाभ समय पर मिल सके।... (व्यवधान)

(इति)

Re: Need to set up a sports stadium of international standard in Lohardaga district, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय सभापति जी, जैसा कि आपको विदित है, मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा (झारखंड) जनजाति बहुल, ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है।... (व्यवधान) यह आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास जारी है। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान यहां के युवाओं की खेल प्रतिभा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गुमला एवं लोहरदगा जिलों के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में देश का मान बढ़ा चुके हैं।... (व्यवधान) आज भी अनेक राष्ट्रीय टीमों में यहाँ के युवक-युवतियाँ खेल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में फुटबाल, हॉकी, एथलेटिक्स आदि खेलों का परंपरागत रूप से प्रचलन हैं। विशेष कर बेटियों की बात करूँ तो उन्होंने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल की अपार प्रतिभाओं से संपन्न यहाँ के युवा आधुनिक खेल परिसरों के अभाव में अभ्यास करते हैं।... (व्यवधान) इन्हें यदि उचित वातावरण और अत्याधुनिक खेल परिसर एवँ प्रशिक्षण मिल जाए तो हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा ओलंपिक सहित अन्य खेलों में देश का मान बढ़ा सकेंगे। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए।... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि लोहरदगा जिले में स्टेडियम के निर्माण कर देश के जनजाति बहुल, ग्रामीण अंचल के खिलाडियों का उत्साह एवं मनोबल को बढ़ाने एवं यहाँ के प्रतिभावान खिलाडियों के लिए अवसरों का सृजन करने में केंद्र सरकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाए। मुझे विश्वास है, देश के युवाओं के प्रेरक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, हमारी सरकार लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर देश के समस्त जनजाति अंचलों को उपहार देकर अनुग्रहीत करेगी।... (व्यवधान) इससे अनेकों अभावों में अपना कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। धन्यवाद।... (व्यवधान)

(इति)

(1430/RPS/SAN)

Re: Release of arrears of payments to hospitals under Ayushman Bharat Yojana in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब, वंचित, बीमारियों से पीड़ित परिवारों को उक्त योजना का लाभ मिला है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और गरीबों के प्रति समर्पण को प्रतिबिंबित करता है।

महोदय, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे अस्पताल हैं, जिनका करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण इन अस्पतालों में गरीबों का इलाज होना बंद हो गया है। ऐसे अस्पताल निम्नलिखित हैं:

1. मेरिक्सी अपरोक्स
2. ब्रह्मनंदा हॉस्पिटल, सरायकेला
3. मेडिटिरिना हॉस्पिटल, सरायकेला
4. गंगा मेमोरियल, जमशेदपुर
5. दया हॉस्पिटल, जमशेदपुर
6. अपूर्वा ईशान, जमशेदपुर
7. साकेत हॉस्पिटल, जमशेदपुर
8. डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड, जमशेदपुर
9. मेहरबाई टाटा, जमशेदपुर
10. डॉक्टर डी. मिश्रा यूरोलॉजी, जमशेदपुर

अत:, महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान कराने की कृपा की जाए, ताकि इन अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों का समुचित इलाज हो सके।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House cannot run like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Members also have ….

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377 - LAID

HON. CHAIRPERSON: Rest of the Members may lay their Matters on the Table of the House.

Re: Need to provide stoppage of Shivganga Express at Gyanpur Road railway station in Uttar Pradesh

श्री रमेश बिन्द (भदोही): मेरे लोक सभा क्षेत्र भदोही के अंतर्गत भदोही और मिर्ज़ापुर जिला आता है जो कालीन और अन्य उद्योगों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और इनका निर्यात विश्व के कई देशों को किया जाता है। ट्रेन नंबर 12559/12560 शिवगंगा एक्सप्रेस वर्तमान में बनारस से दिल्ली के बीच चलती है और सिर्फ कानपुर अथवा प्रयागराज स्टेशन पर इसका ठहराव है। भदोही जिले के अंतर्गत आने वाले ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेन जैसे चौरी चौरा एक्सप्रेस और स्वतंत्र सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव है और विगत कई वर्षों से यह मांग है कि शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप मिर्ज़ापुर और भदोही जिले के व्यापारी, छात्र और उपचार के लिए यात्रा करने वाले मरीज़ों को राहत मिलेगी और मेरे लोक सभा क्षेत्र भदोही के आर्थिक विकास और कालीन उद्योग को और भी गति मिलेगी। मेरा सरकार और रेल मंत्रालय से आग्रह है कि शिवगंगा एक्सप्रेस का ठहराव ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की मांग को तत्काल स्वीकृति दी जाए जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र के निवासियों को उद्योग, शिक्षा या उपचार के लिए यात्रा करना आसान होगा और पूर्वांचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने के अतिरिक्त रोज़गार भी उत्पन्न होगें।

(इति)

Re: Introduction of air conditioned rail ambulance

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव):कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में एम्बुलेंस के अभाव के कारण बहुत सारे मरीज़ों की मृत्यु हुई और NCRB के अनुसार प्रतिदिन 24012 लोग समय पर सहायता ना मिलने से अपनी जान गवा देते है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का लक्ष्य रखा है जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है लेकिन आज भी ग्रामीण, किसान और गरीब परिवारों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की आवशयकता पड़ती है और कई बार जब बीमारी गंभीर हो तो उसको उपचार हेतु अन्य शहरों में भी जाना पड़ता है। रेलवे ने 2017 में air conditioned rail ambulance का प्रावधान किया था जिसमे एक समय पर 50 मरीज़ यात्रा कर सकते है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार किसानों के हित के लिए किसान रेल का संचालन हो रहा है उस प्रकार रेल एम्बुलेंस का प्रावधान हर रेलवे जोन में किया जाए जिससे मरीज़ों को आपातकालीन स्थिति में गैर सरकारी एम्बुलेंस पर निर्भर ना होना पड़े जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान होता है और बहुत सारे परिवार इसके परिणामस्वरूप क़र्ज़ में डूब जाते है। रेलवे एम्बुलेंस के संचालन से ग्रामीण और गरीब परिवार के मरीज़ रेल के माध्यम से उपचार सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। (इति)

Re: Setting up of an Airport at Chengannur in Mavelikkara parliamentary Constituency

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kerala holds an important position in the nation's economy as the largest recipient of external remittance, home to the largest diaspora and an important tourist destination. The central Travancore region composed of Kottayam, Pathanamthitta, Idukki and alappuzha is of immense significance as the hub of NRIs and Expats both in terms of numbers and movement and world renowned tourist destinations. However, a long standing demand of establishing an international airport for serving central travancore region, has been left unfulfilled. The demand for an airport at Chengannur is rising now as Chengannur is an ideal location for creating a Hub and Spoke network of access based development of the entire central Travancore region and to facilitate international travel and tourism. I request the government to depute an expert committee to conduct a detailed feasibility study and technical review of an airport project at Chengannur that falls within my Loksabha constituency Mavelikkara. (ends)

Re: Construction of a bridge over river Bhavani in Palakkad district, Kerala

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The death of tribal infant children is going on unabated in Attappadi Taluk in Palakkad district. Again on 14.7.2022, death of an infant child of a couple of Murugala ooru of this taluk took place. Tribals of this taluk have to walk many kilometres to avail of medical facilities. There are no basic facilities available to the tribal hamlets falling in the forest areas and no vehicle can reach these hamlets in case of emergency. There is an urgent need to construct a bridge over river Bhavani and road leading to the proposed bridge, so that these people could avail medical treatment. I have raised issues concerning the plight of these tribal people many times in this august House, including a demand to set up a development authority to take care of this tribal people. Therefore, I urge upon the government to take all measures to prevent the death of children in Attappadi taluk urgently by creating all necessary basic facilities which can be possible by setting up a development authority.

(ends)

Re: Plight of traditional Indian Fishermen

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Millions of Indian traditional fishers are facing a threat of extinction due to many reasons. The natural calamities and climate change have already posed a huge challenge in front of them. And also the lives and livelihoods of traditional marine fishers are in serious trouble because of the policies of government. The recent Geneva Ministerial Summit of WTO decided to drop all subsidies for fishing and allied activities which will harm our fisheries severely. India was expected to protest against this injustice done by WTO, instead it agreed to it. This will wash out our fishers from our coasts. The excessive price hike of Kerosene became a choking issue among fishers. In Kerala itself, the price of Kerosene jumped to Rs. 102. The Kerosene quota for fishers has been cut down to 129 litres per month from 450 litre per month. And the state quota has also been cut down by the Union government. This is outrageous and condemnable. The GOI must be awakened to these issues impacting one of the most segregated communities in the country. Our fishers are in a desperate need of help to survive.

(ends)

Re: Need to operate a regular reserved train between Coimbatore/Mettupalayam and South Tamil Nadu

SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): Lord Murugan temple in Palani is one of the most visited pilgrimage centres in India. Millions of pilgrims every year from other countries and from India (especially from Tamil Nadu & Kerala) visit Palani temple. Palani serves as one of the nearest rail head for world famous tourist hill destination “Kodaikanal”. Also, Dindigul is the one of municipal corporations of Tamil Nadu which has various industries and educational institutions. Oddanchatram is a commercial town in Dindigul constituency and has one of the largest vegetable markets in India. I would like to highlight that there is no regular reserved train operating at present between Coimbatore / Mettupalayam and South Tamil Nadu through the shortest rail route (via. Palani). The service of trains is going to end by this week (1st July, 2022). I request the Hon’ble Railway Minister for making the services of train permanent in the interest of the general public. (ends)

Re: RINL tender relating to coke oven batteries

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): RINL had turnaround last year and broke all previous records, be it production, sales, export, etc., and earned a profit of 835 crores and gross margin of 3,575 crores which was best ever since setting up of the plant. So, instead of encouraging it to do better, it seems, GOI is pulling it down in every possible way. Firstly, RINL is not being supplied coal due to Railways not giving rakes for coal transportation. Secondly, GOI has, on 25-06-2022, issued tender inviting interested parties to come and take over 2 coke oven batteries on contract basis. Batteries play an important role in steel production and handing over batteries under the garb of comprehensive battery maintenance is nothing but privatization of RINL which is not acceptable to workers and people of AP since more than 500 workers are working in each coke oven batteries.

Hence, I demand to immediately withdraw tender issued by Government.

(ends)

Re: Promoting export of agricultural products

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): With only 2.4% of the world's land and 4% of its water resources, India supports 17.84% of the world's population and 15% of the livestock population. It is encouraging that India's role in global agricultural exports is steadily increasing. According to World Trade Organization trade data, India’s agricultural and allied exports during 2019-20 were Rs. 2.52 lakh Crores. India's share of global agricultural exports has increased from 1% a few years ago to 3.1% in 2019. Recent growth rates show that agri-food production is increasing faster than domestic demand, and the volume of surplus for export is increasing rapidly. This provides scope and opportunity for capturing overseas markets in order to earn money. India needs a direct export channel for farmers to revitalize the entire value chain, from export-oriented farm production and processing to transportation, infrastructure, and market access. A framework for sustainable agriculture, on the one hand, and a viable agriculture export policy on the other hand have a mutually beneficial relationship.

Hence, it is necessary to develop a policy that will directly benefit the farmers by providing them with vital opportunities to export their products overseas.

(ends)

Re: Need to develop sports infrastructure and facilities under 'Khelo India Yojana' in Goplaganj district, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान केंद्र प्रायोजित "खेलो इंडिया योजना" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिससे जनता, इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से खेल-कूद की क्षमता का उपयोग कर सके। खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल के बुनियादी ढांचे की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और उन्नयन के माध्यम से खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना; खेल के मैदान का विकास करना; सामुदायिक कोचिंग विकास; सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना; ग्रामीण और स्वदेशी खेलों के साथ-साथ स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एक मजबूत खेल प्रतियोगिता संरचना की स्थापना, दिव्यांगजनों के लिए खेल तथा महिला खेल और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन करना शामिल है। महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के गोपालगंज जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और अधिक महत्व वाले क्षेत्रों के निवासियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करके ग्रामीण विकास लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता है। " खेलो इंडिया योजना" से खेल के बुनियादी ढांचे और खेल के मैदान की सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से निश्चित रूप से बिहार के जिला गोपालगंज में ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों का विकास होगा। महोदय, मैं माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बिहार के गोपालगंज जिला को खेलो इंडिया योजना के तहत शामिल किया जाए ताकि खेलकूद की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे और खेल के मैदानों की व्यवस्था की जा सके और लोगो को खेल गतिविधियां में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जा सकें। (इति)

Re: Payment of arrears of honorarium to Madrasa teachers and also increase the amount of honorarium being paid to them

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): उत्तर प्रदेश के मदरसों में कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को Scheme for Providing Education to Madrasas/Minorities (SPEMM) योजना के अन्तर्गत सरकार ने 2022 में कुछ महीनों के लिए वेतन का भुगतान किया है, लेकिन 2017 से 2021 तक उनके लंबित बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षकों को सालों से मानदेय वेतन नहीं मिलने की वजह से इन शिक्षकों में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। मदरसा शिक्षकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है लगातार हो रही मदरसा आधुनिकीकरण ने मदरसा शिक्षकों को आघात पहुँचाया है। सरकार की तरफ से अभी तक न तो बकाया मानदेय दिया गया है और न ही शासन-प्रशासन का नुमाइंदा कोई सुध ले रहा है। वेतन नहीं मिलने से मदरसा शिक्षक भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जिससे प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का नारा बेमानी साबित हो रही है।

सरकार से मेरी मांग है की इन शिक्षकों का केंद्र व प्रदेश सरकार पर अब तक कितना बकाया राशि है ये स्पष्ट करें एवं तत्काल केंद्र व प्रदेश पर लंबित इन का मानदेय जारी कराया जाय, महंगाई को देखते हुए मानदेय बढ़ाया जाय अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इन को भी पूरा मानदेय प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान किया जाय। (इति)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، اتر پردیش کے مدرسوں میں کام کرنے والے مدرسہ آدھونیکی کرن ٹیچرس کو Scheme for Providing Education to Madrasas / Minorities (SPEMM) یوجنا کے تحت سرکار نے 2022 میں کچھ مہینوں کے لئے تنخواہ کی ادائیگی کی ہے، لیکن 2017 سے 2021 تک انکے لمبِت بقایہ کا بھگتان نہیں کیا گیا ہے۔

ٹیچرس کو کئی سالوں سے ماندے تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے ان ٹیچرس میں مرکزی و صوبائی سرکاروں کے خلاف بہت غصہ ہے۔ مدرسے کے ٹیچرس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ ماندے نہ ملنے کی وجہ سے لگاتار ہو رہی ٹیچرس کی موتوں نے ٹیچرس کو گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ سرکار کی طرف سے ابھی تک نہ تو بقایہ ماندئے دیا گیا ہے اور نہ ہی شاسن ، پرشاسن کا کوئی نمائدہ کوئی سُدھ لے رہا ہے۔ تنخواہ نہ ملنے کی ٹیچرس بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ جس سے وزیرِ اعظم کے سب کا ساتھ سب کا وِکاس کا نارہ بے معنیٰ ثابت ہو رہے ہے۔

سرکار سے میری مانگ ہے کہ ان ٹیچرس کا مرکزی و صوبائی سرکاروں پر کتنا بقایہ ہے واضح کریں اور مرکزی و صوبائی سرکاریں جلد سے جلد ان کا بقایہ جاری کرائیں، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ماندئے بڑھایا جائے دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح ان کو بھی پرا ماندئے ہر مہینے دئے جانے کا پراودھان کیا جائے۔ شکریہ..

Re: Merger of schools in Andhra Pradesh

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): AP government is playing with the future of our children by merging schools and reducing the number of teacher posts. Classes 1, 2 are being merged with anganwadis. Classes 3, 4, 5 are being integrated with high schools. Parents don't know if the school in which their child is studying in will exist tomorrow or not, leading to uncertainty about their child's future. Pupil teacher ratio will be worsened, defeating the 'very concept of quality education'. AP Govt. is still going ahead with the merger despite protests by Parents and students. AP is using NEP as an excuse for all this mess. However, disintegration of primary schools has not been recommended by NEP or RTE. AP Govt. is allegedly lying to the people. Hence, I request the Centre to take action regarding the act of AP state to stop this mindless merger of schools, which is destroying the future of our students.

(ends)

Re: Sanctioning of a Central Agriculture University in Tamil Nadu

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Tamil Nadu is one of the key food-producing states in the country with nearly 70% of the population engaged in agriculture and allied activities. Also, Tamil Nadu holds a significant position with respect to the output of agricultural produce. Hence, crucial initiatives and interventions are needed to develop sustainable farming systems for improving productivity and profitability in agriculture and allied sectors. Also, there is a need to train farmers in modern and advanced agricultural technology.

Sir, to promote excellent strategic & anticipatory research in the field of agriculture, the establishment of an institution of higher learning is vital. Such an institute will serve as an important link in the chain for converting agriculture and allied vocations, into profitable enterprises, and offering food and nutritional security for our nation.

Hence, I urge the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers welfare, through you Sir, to sanction a Central Agriculture University in Tamil Nadu, that will serve as a centre of excellence in teaching, research and extension education in the field of agriculture and allied sectors.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

1433 hours

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.